

कार्यसूची सं.	1
बैठक का दिनांक	20.08.2019
बैठक सं.	68

दिनांक 15 मई, 2019 को आयोजित 67 वीं SLBC बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

- दिनांक 15 मई, 2019 को आयोजित 67 वीं एस एल बी सी बैठक के कार्यवृत्त सभी संबंधित कार्यालयों को संप्रेषित किए गए हैं।
- सभा के द्वारा उपर्युक्त बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है क्योंकि इस संबंध में किसी भी कार्यालय /विभाग द्वारा किसी प्रकार के संशोधन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

कार्यसूची सं.	2
बैठक का दिनांक	20.08.2019
बैठक सं.	68

पूर्व मे आयोजित एस एल बी सी बैठक में लिये गये निर्णय पर कृत कार्यवाही रिपोर्ट

राज्य सरकार से संबंधित मामले

क्र.स.	से लंबित	विषय	वर्तमान स्थिति
1	15.06.2018	Dedicated Certificate Officer की नियुक्ति का मामला	Dedicated Certificate Officer एवं अन्य कर्मचारियों के कार्यालयीय खर्च की प्रतिपूर्ति बैंको द्वारा किये जाने के राज्य सरकार के सुझाव के अलोक में बैंको द्वारा लिए गए निर्णय से राज्य सरकार को पत्रांक SLBC/18-19/53 दिनांक 15.06.2018 के माध्यम से अवगत करा दिया गया था, जिसमे बैंकों द्वारा वसूली गयी राशि से 5% की राशि सरकारी कोष में जमा करने की सहमति दी गयी थी। पूर्व में तत्कालीन विकास आयुक्त के आदेशानुसार बैंको से पुनः इस पर परिचर्चा की गयी परन्तु व्यवहारिक कठिनायियों के कारण बैंको द्वारा कार्यालयीय खर्च की प्रतिपूर्ति कर पाने में असमर्थता व्यक्त की गयी। किसी सर्वमान्य निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाने के कारण इस विषय को अगले बैठक से समाप्त कर दिए जाने का प्रस्ताव SLBC द्वारा पिछली बैठक के दौरान किया गया था परन्तु RBI के सुझाव के आधार पर इसे पुनः राज्य सरकार के पास लंबित मामलों में शामिल किया जा रहा है और सरकार से आग्रह है कि इस सम्बन्ध में ज्यादा NPA वाले बैंको के नियंत्रक प्रमुखों के साथ बैठक कर कोई सर्वमान्य हल ढूंढा जाये।
2	23.07.2018	बैंको को सरकारी भूमि का आवंटन का मामला	राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 में SLBC एवं अन्य बैंको को आवंटित किये जाने वाली भूमि के क्रय मूल्य में किये गए परिवर्तन पर विस्तृत चर्चा हेतु विभाग द्वारा एक बैठक का आयोजन किया जाना प्रस्तावित था परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई बैठक नहीं हो पाई है।
3	27.11.2017	SARFAES I के अंतर्गत physical possession के लिए लंबित cases	बैंको से SLBC के पोर्टल पर प्राप्त सूचना बैंको द्वारा ऋणियों के नाम के साथ दिए गए जिलावार सूचना से काफी भिन्न है। SLBC द्वारा नाम के साथ दी गयी pending रिपोर्ट की सूची राज्य सरकार को दिनांक 07.05.2019 दी गयी है।
4	23.07.2018	land records को	राज्य में land records को अद्यतन (dizitization) किये जाने के बावजूद इसके regular updation नहीं किये जाने के कारण

		अद्यतन किया जाना	वास्तविक जमीन मालिक के सही पहचान में आ रही कठिनाई के समाधान हेतु राज्य सरकार से सहयोग अपेक्षित है।
5	09.02.2017	वित्तीय शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में	पिछली बैठक के दौरान इस मुद्दे पर RBI के सहायक महाप्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि CBSE, RBI, SEBI, IRDA एवं PFRDA के द्वारा वित्तीय शिक्षण पर तैयार किए गए वर्कबुक को राज्य के स्कूलों में नियमित पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल कराये जाने के मुद्दे को RBI के सुझाव के आलोक में पुनः शामिल किया जा रहा है और इस विषय पर सरकार से वर्तमान वस्तुस्थिति की जानकारी अपेक्षित है।
6.	22.07.2019	किसान क्रेडिट कार्ड से छूटे हुए योग्य किसानों का ब्योरा बैंको को उपलब्ध करवाना	केसीसी saturation का अभियान जारी है। इस अभियान के पूर्ण सफलता के लिए SLBC द्वारा राज्य सरकार के कृषि विभाग से निवेदन किया गया है कि जिन योग्य किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है, उसका ब्योरा बैंकों को मुहैया कराए जाँ ताकि उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड तय सीमा में दिया जा सके। पूर्व में भी बैंकों द्वारा यह आग्रह किया जाता रहा है परन्तु विभाग द्वारा संबन्धित सूची अभी तक अप्राप्त है।

बैंक से संबंधित मामले

बैंकों से संबंधित मामलों को 61वीं SLBC की बैठक से SLBC द्वारा ATR के रूप में discuss किये जाने का प्रावधान किया गया है। पिछली SLBC की 67 वीं बैठक के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा की गई थी, उन मुद्दों को सभी संबंधित बैंकों एवं LDMs को उनके द्वारा उचित कार्यवाही करने के लिए ATR के format में भेजा गया था, जिससे संबंधित compiled रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के पूर्व उन बैंकों एवं LDMs का उल्लेख जरूरी है जिन्होंने बार-बार लिखित एवं मौखिक आग्रह के बावजूद SLBC को ATR प्रेषित नहीं किया है। ये बैंक हैं- Bandhan Bank, Federal Bank, Indus Ind Bank, J & K Bank, Karur Vaisya Bank, Kotak Mahindra Bank, Laxmi Vilas Bank, South Indian Bank और Yes Bank.

विस्तृत रिपोर्ट पृष्ठ सं-2 (a) से 2 (e) पर संलग्न है।

कार्यसूची सं.	3
बैठक दिनांक	20.08.2019
बैठक सं.	68

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के महत्वपूर्ण संकेतक

(Rs in crores)

Sl. No	KEY INDICATORS	30.06.2018	31.03.2019	30.06.2019	Bench Mark
1	Deposit	198214.28	218100.64	219466.95	
	CASA Deposit	90731.75	99896.90	98048.17	
2	Credit	86863.17	95562.14	94952.77	
3	Credit as per place of utilization* & RIDF**	30782.35	29465.43	28820.18	
4	Total Credit	117645.52	125027.57	123772.95	
5	CD Ratio	59.35	57.33	56.40	60
6	Priority Sector Advances (PSA)	45573.29	52924.75	52754.89	
7	Share of PSA to Total Advances (%)	52.47	55.38%	55.56	40
8	Agricultural Advances	13510.82	14864.80	14821.83	
9	Share of Agricultural Advances to Total Advances (%)	15.55	15.56%	15.61	18
10	i. Micro & Small Enterprises Advance	20323.37	24189.37	24508.50	
	ii. Share of Micro & Small Enterprises to Total Advances (%)	23.44	25.31%	25.81%	
	iii. Share of Micro Enterprises in MSE	59.90	56.60%	57.19%	
11	Advances to Weaker Sections	14937.72	16334.11	16365.23	
12	Share of Weaker Section Advances to Total Advances (%)	17.19	17.09%	17.24	10
13	DRI Advances	31.15	32.59	34.51	
14	Share of DRI Advances to Total Advances of last March (%)	0.04	0.04%	0.04%	1
15	Advances to Women	11455.11	13027.82	13334.22	
16	Share of advances to women in Total advances (ANBC) (%)	13.19	13.63%	14.04%	5
17	Advances to Minorities (Amount)	5806.86	6113.46	6064.21	
18	Share of Advances to Minorities under PSA (%)	12.74	11.55%	11.50%	15
19	Gross N.P.A	5099.35	5711.86	5866.98	
	Provision	2571.05	2820.73	3025.41	
	Net NPA	2528.30	2891.13	2841.57	
	Gross NPA Percentage	5.87%	5.98%	6.18%	
	Net NPA Percentage	2.91%	3.02%	2.99%	
20	Branch Net-Work (in no.)-Rural	1498	1486	1484	
	Semi-Urban	785	776	771	
	Urban	729	834	842	
	Total	3012	3096	3097	
	BranchNetwork-Smal Finance Bank			65	

	Banks	Payment			22	
		Total Branch including SFB			3184	
21		ATM installed in Jharkhand	3471	3367	3420	
		ATM-Small Finance Bank			26	
		Total ATM			3466	

*Annexure- V, As per Annex - I, Annex-II, Annex-III, Annex-IV, Annex -XIX

पर्यवेक्षण

जमा वृद्धि (Deposit Growth)

झारखंड राज्य में बैंकों की सकल जमा में पिछले एक साल में, यानि 30 जून, 2018 से 30 जून 2019 तक रूपये 21252.67 करोड़ की वर्ष-वार वृद्धि हुई है | वर्ष-दर-वर्ष सकल जमा में 10.72 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है |

ऋण वृद्धि (Credit Growth)

राज्य में बैंकों के कुल क्रेडिट में पिछले एक साल में रूपये 7316.42 करोड़ की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई | वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की दर 8.06 प्रतिशत दर्ज की गई है |

क्रेडिट – जमा अनुपात (C.D Ratio)

30.06.2018 (59.35%) की तुलना में 30.06.2019 (56.40%) में CD ratio में गिरावट दर्ज की गई है, परन्तु पिछली कई तिमाही में बैंकों का सीडी अनुपात में गिरावट हो रही है। CD ratio जून 2019 में 56.40% रह गया है, जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 60% से काफी कम है | मार्च'19 के तुलना में कुल क्रेडिट में 609.37 करोड़ एवं RIDF में 362.67 करोड़ की गिरावट दर्ज हुई है जबकि कुल जमा में 1366.31 करोड़ की वृद्धि हुई है। जून'18 एवं जून'19 के तुलना करने पर कुल जमा में 21252.67 करोड़ की वृद्धि के समक्ष कुल ऋण में मात्र 7316.42 की वृद्धि हुई है तथा **Credit as per place of utilization & RIDF** में 1962.17 करोड़ की गिरावट दर्ज हुई है। सभी बैंकों को इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है |

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम (PSA)

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 15.75% की वृद्धि दर्ज की गयी है। वर्तमान में समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम कुल अग्रिम का 55.56% है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 40 प्रतिशत से ज्यादा है।

कृषि अग्रिम (Agriculture Credit)

31 मार्च 2019 को कृषि अग्रिम रु. 14864.80 करोड़ था जो कुल अग्रिम का 15.56 प्रतिशत था। यद्यपि पिछली तिमाही में कृषि ऋण के अंतर्गत रु. 1494.49 करोड़ संवितरित किये गए हैं, परंतु वर्तमान में कृषि क्षेत्र का अग्रिम कुल अग्रिम का 15.61 % है, जो कि राष्ट्रीय बेंचमार्क 18% से कम होने के कारण एक चिंतनीय प्रश्न है और बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में अपेक्षित ऋण प्रवाह नहीं किये जाने की ओर स्पष्ट संकेत करता है | लगभग प्रत्येक SLBC की त्रैमासिक बैठक एवं कृषि उपसमिति में इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की जाती रही है परंतु अब यह लाजिमी ही गया है कि सभी बैंको एवं अन्य हितधारकों को विशेष कार्ययोजना बनाकर कृषि ऋण में वृद्धि करने के लिए अथक प्रयास करना पड़ेगा |

कमजोर वर्ग (Weaker Section)

30 जून 2019 तक झारखण्ड राज्य में कमजोर वर्ग को रूपये 16365.23 करोड़ (17.24 प्रतिशत) का ऋण दिया गया है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 10 प्रतिशत से बेहतर है। वर्ष दर वृद्धि 9.56 % दर्ज की गई है।

महिलाओं को ऋण (Advance to Women)

30 जून 2019 तक महिलाओं को दिये गए ऋण का कुल शेष (O/S) रू. 13334.22 करोड़ है, जो की कुल अग्रिम का लगभग 14.04% है | यह राष्ट्रीय बेंचमार्क 5% से ऊपर है | वर्ष दर वृद्धि 14.09% दर्ज की गई है।

अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण (Advance to Minority Community)

30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण रूपये 6064.21 करोड़ है | यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का 11.50% है, जो मानक 15 प्रतिशत से कम है | वर्ष दर वृद्धि 4.43 % दर्ज की गई है। इसमें अपेक्षित सुधार लाने के लिए सभी बैंकों को ध्यान देने की आवश्यकता है |

30 जून 2019 को राज्य का ऋण-जमा अनुपात

भारतीय रिजर्व बैंक के **MASTER CIRCULAR. No - RPCD.CO.LBS.BC.No. 9/02.01.001/2014-15**, दिनांक 01.07.14 के अनुसार बैंकों का ऋण जमा अनुपात का मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर होने वाले उपयोग और आर आई डी एफ के अनुसार किया जाना है।

तदनुसार, झारखण्ड राज्य का ऋण –जमा अनुपात निम्नवत है :-

(Rs in crore)

DETAILS		30 th June, 2018	30 th June, 2019	
Aggregate Deposits		198214.28	219466.95	
CORE ADVANCES	86863.17		94952.77	
As per place of Utilization	25752.98		22865.38	
RIDF	5029.37		5954.80	
NET ADVANCES	117645.52		123772.95	
ऋण-जमा अनुपात		59.35		56.40

(परिशिष्ट-4, परिशिष्ट - 5)

नोट : कृपया ऋण – जमा अनुपात का विस्तृत विश्लेषण हेतु संलग्नक का संदर्भ लें जिसमें विभिन्न पैरामीटर ग्रामीण/अर्द्धशहरी/शहरी केन्द्र, बैंकवार और जिलावार समीक्षा आदि से संबंधित पूर्ण विवरण संलग्न है।

हम यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करना चाहेंगे कि मार्च 2019 की तुलना में राज्य का CD Ratio 57.33% से कम होकर जून 2019 में 56.40% रह गया है | बैंको के समग्र ऋण में गिरावट दर्ज हुई है और हमारा core CD Ratio 43.82% से घटकर 43.27% हो गया है। पिछली तिमाही से HDFC Bank द्वारा Place of Utilisation के तहत रु 3657.34 करोड़ दर्शाया गया था जिसे इस तिमाही के अंत में शून्य दर्शाया गया है, जिसके कारण राज्य के CD Ratio में कमी आई है |ICICI बैंक के CD Ratio में 44% की गिरावट दर्ज हुई है। पिछले तिमाही में ICICI Bank के कुल जमा में 455 करोड़ की वृद्धि हुई है परंतु में कुल ऋण में 1163 करोड़ की गिरावट दर्ज हुई है। इलाहाबाद बैंक के CD Ratio में 5% की गिरावट दर्ज हुई है।

कार्यसूची सं.	4
बैठक का दिनांक	20.08.2019
बैठक संख्या	68

4.1 वार्षिक ऋण योजना 2019-20 के तहत उपलब्धियों की समीक्षा : 30 जून 2019 तक

30 जून 2019 की स्थिति के अनुसार वार्षिक ऋण योजना 2019-20 के क्रियान्वयन में बैंकों का पिछले वर्ष की तुलना में सेक्टर वार उपलब्धि:

(रू करोड़ में)

SECTOR	ANNUAL TARGET (2018-19)	ACHIEVEMENT IN AFY 2018-19		ANNUAL TARGET (2019-20)	ACHIEVEMENT IN AFY 2019-20	
	AMT.	AMT	AMT.	AMT.	AMT	%
1	5	6	5	5	6	7
Agriculture	8336.60	1008.29	12.09	9026.04	1494.5	16.56%
MSME	8560.35	3086.26	36.05	10269.11	4413.9	42.98%
OPS	4213.60	694.50	16.48	2817.51	525.67	18.66%
Total Priority	21110.55	4789.05	22.68	22112.66	6434.07	29.10%
Non Priority	8773.34	3729.85	42.51	11921.92	3187.37	26.74%
Total	29883.89	8518.90	28.50	34034.58	9621.44	28.27%

कृषि ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कुल अग्रिम एवं CD ratio में विभिन्न जिलों एवं बैंको द्वारा प्राप्त किये गए उपलब्धि प्रतिशत को पृष्ठ सं-7(a) में दर्शाया गया है।

टिप्पणियां :

- ✚ वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम तिमाही दौरान वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध **28.27 %** समग्र ऋण का संवितरण हुआ है। यह उपलब्धि पिछले वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में हुई **28.50 %** संवितरण के बराबर ही है, परंतु सभी बैंकों के सामूहिक प्रयास से आगामी महीनों में इसमें अपेक्षित वृद्धि लायी जा सकती है।
- ✚ कृषि क्षेत्र में कुल वार्षिक योजना के विरुद्ध केवल 16.56 % ऋण का संवितरण ही हो पाया है। कृषि क्षेत्र में ऋण संवितरण की स्थिति में और अधिक सुधार की आवश्यकता है। सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है की वे नाबार्ड के तत्वाधान में हुए SLBC-agriculture sub-committee की बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों जैसे कि-कम से कम 30% कृषि ऋण का संवितरण मियादी ऋण के रूप में सुनिश्चित करना, दुग्ध उत्पादन, मतस्य पालन, मुर्गी पालन एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों के लिए ऋण देना इत्यादि तथा एरिया डेवलपमेंट स्कीम का अनुपालन अपनी शाखाओं के माध्यम से पूरी दृढ़ता के साथ लागू कराने का प्रयास करें ताकि कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढ़ाया जा सके।
- ✚ MSME sector में इस वित्तीय वर्ष में बैंकों द्वारा MSME के वार्षिक बजट के विरुद्ध 43% की उपलब्धि सराहनीय है।
- ✚ 2019-20 के लिए दिये गए ACP के विरुद्ध बैंकवार एवं जिलावार हुई उपलब्धि को annexure-6 में दर्शाया गया है एवं Agriculture Loan में बैंकवार एवं जिलावार segment wise संवितरण और o/s का रिपोर्ट annexure-7 में दिया गया है।

कार्यसूची सं.	5
बैठक का दिनांक	20.08.2019
बैठक संख्या	68

5. REVIEW OF LENDING ऋण की समीक्षा

5.1. कृषि एवं किसान क्रेडिट कार्ड

राज्य में सभी बैंकों का कुल कृषि साख 30.06.2019 की स्थिति के अनुसार रु. 14821.83 करोड़ है जो सकल ऋण का 15.61 % है। यह राष्ट्रीय मानक 18 प्रतिशत से कम है। बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों, नाबार्ड एवं अन्य संबंधित हितधारकों के सामूहिक प्रयास से इसे पुनः बेंचमार्क 18% से ज्यादा किये जाने का यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए।

झारखण्ड में के सी सी की स्थिति (STATUS OF KCC IN JHARKHAND)

(Amt. In Crores)

Type Of Banks	Disbursement during 2019-20		Outstanding In KCC A/Cs As of 30.06.2019	
	A/C	Amt.	A/C	Amt.
Public Sector Banks	54739	191.21	1297006	5024.40
Pvt. Banks	8679	33.85	48572	221.06
Total	63418	225.06	1345578	5245.5
RRB	14336	96.06	389754	1738.60
Co-op Banks	121	0.80	11002	30.34
Total	77875	321.92	1746334	7014.40

(KCC से संबंधित प्रतिवेदन annexure-8 में उल्लिखित है)

- ❖ सभी सामान्य के सी सी खातों को Smart K.C.C खातों में परिवर्तित कर उन खातों में आवश्यक तौर पर Rupay Card जारी कर देना था, ताकि यह ATM एवं POS में भी कार्य कर सके। दिनांक 30.06.2019 तक बैंकों द्वारा दिये गए आंकड़े के अनुसार कुल 1540921 eligible KCC खातों में से 1364708 खातों में रूपे कार्ड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है जिसके विरुद्ध 1327364 खातों में (97.26%) rupay debit card निर्गत किये गए हैं।

(विवरण पृष्ठ सं-8(a) एवं 8(b) में संलग्न है।

5.2. (क) सुक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमों का वित्त पोषण

5.2.1. सुक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमों का वित्त पोषण (एम एस एम ई)

(Accounts in thousands) (Amt. in crore)

Sl. No.	Particular	Outstanding position as at the end of		
		June 2018	June 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	
MICRO & SMALL ENTERPRISES				
1	Micro Enterprises	Accounts	539	697
		Amount	12172.70	14018.59
2	Small Enterprises	Accounts	46	58

		Amount	8150.67	10489.91
3	Total Micro and Small Enterprises (MSE sector)	Accounts	585	765
		Amount	20323.37	24508.59
MEDIUM ENTERPRISES				
4.	Total of Medium Enterprises	Accounts	07	09
		Amount	1885.35	2426.28
MSME				
TOTAL MSME (PRIORITY SECTOR ADVANCES)		Accounts	592	774
		Amount	22208.72	26934.78
5.	a.	Share of Credit to Micro Enterprises in total credit to MSE sector	Percent share of amounts (stipulation: 60%)	59.90% 57.20%
	b.	Share of credit to MSE sector in NBC/ ANBC	Percent share of amount	23.44% 25.81%

(MSME रिपोर्ट –annexure-9)

COVERAGE UNDER CGTMSE (for eligible Loans Upto Rs. 2.00 Crore in MSE)
(Position as on 30.06.2019)

(A/C in 000, Amt.in Cr.)

Eligible MSE loan up to Rs. 2.00 Crore		Coverage under CGTMSE	
TOTAL		TOTAL	
A/C	Amt	A/C	Amt.
556	19642.13	115	7961.82

(रिपोर्ट पृष्ठ सं- 9 a में सलग्न है)

टिप्पणियां

- ✚ झारखंड में कुल एमएसई में माइक्रो सेक्टर क्रेडिट की हिस्सेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार 60% की बेंच मार्क के विरुद्ध जून, 2019 में 57.20 % है।
- ✚ बैंको द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार ,झारखण्ड राज्य में, रु. 2 करोड़ की सीमा के अंदर कुल 5.56 लाख (लगभग) MSE ऋण खातों हैं, जो cgtmse coverage के लिए eligible हैं, परंतु इनमें से केवल 1.15 लाख (लगभग) ऋण खातों में, यानी कि सिर्फ 20.68% खातों में ही CGTMSE कवरेज लिया गया है। **RBI एवं SLBC के बार बार आग्रह के बावजूद बैंको द्वारा इसकी reporting में सुधार नहीं किया जा रहा है।**
- ✚ PSB Loans in 9 Minutes से सम्बंधित रिपोर्ट पृष्ठ संख्या-10 (b) & 10 (c) में दिया गया है।

5.2 (ख) “प्रधानमंत्री मुद्रा योजना”

दिनांक 8 अप्रैल,2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई | यह योजना मुख्यतः गैर-कृषि क्षेत्र के छोटे उद्यमियों को बैंक द्वारा वित्त पोषण के लक्ष्य से शुरू की गई थी | परंतु वर्तमान में DFS, Ministry of Finance, GOI के पत्रांक - 29/2/2016-IF-2 दिनांक 23.06.2016 के द्वारा कृषि क्षेत्र के Allied Activities -e.g. Pisciculture, beekeeping, poultry, diary, fishery, agriclincs & agribusiness centres, food & agro processing एवं इन गतिविधियों को सहारा देने वाली वैसी सेवाएँ जो जीविकोपार्जन अथवा आय अर्जन को promote करती हैं, इत्यादि को भी 01.04.2016 से PMMY के तहत शामिल कर लिया गया है | PMMY योजना के तहत दिये जाने वाले सभी ऋणों का NCGTC (National Credit Guarantee Trustee Co Ltd) द्वारा guarantee cover (CGFMU-Credit Guarantee for Mudra Unit) सुनिश्चित किया गया है |

इस योजना की राज्य में प्राप्त उपलब्धि निम्नलिखित है:

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में झारखण्ड की उपलब्धि (01.04.19 से 30.06.19 तक)

(राशि करोड़ में)

	शिशु		किशोर		तरुण		TOTAL	
	NO	AMT	NO	AMT.	NO	AMT.	NO	AMT.
Sanctioned	75201	273.73	9758	202.33	2559	206.50	87518	682.57
Disbursed	75135	271.54	9741	193.27	2548	186.13	87424	650.94

MUDRA पोर्टल पर दिये गए आंकड़ों के अनुसार राज्य में Micro Finance Institutions के द्वारा लगभग 345921 खातों में रु 1173.18 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है और 345921 खातों में रु 1062.99 करोड़ की राशि वितरित की गई है। इस तरह MUDRA योजना के तहत राज्य में अब तक कुल 433439 खातों में रु 1855.75 करोड़ की राशि का संवितरण हुआ है।

MUDRA पोर्टल पर दिये गए आंकड़ों के अनुसार राज्य में सभी बैंको एवं Micro Finance Institutions के द्वारा सम्मिलित रूप से इस योजना की राज्य में प्राप्त उपलब्धि निम्नलिखित है :

	शिशु		किशोर		तरुण		TOTAL	
	No.	AMT	No.	AMT.	No.	AMT.	No.	AMT.
Sanctioned	403399	1090.04	25884	422.28	4156	343.42	433439	1855.75
Disbursed	403333	1071.49	25867	354.00	4145	288.44	433345	1713.93

(रिपोर्ट पृष्ठ सं-10 (a) एवं 10(b) में संलग्न है)

5.2 (ग) स्टैंड अप इंडिया ऋण योजना

स्टैंड अप इंडिया ऋण योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य की उपलब्धि 30.06.2019 तक SIDBI के पोर्टल के आधार पर इस प्रकार है-

Total Beneficiaries	Women Beneficiaries	Male Beneficiaries	Out of total Beneficiaries, SC/ST Beneficiaries	Loan Sanctioned Amt (Rs in Cr)
22	21	01	00	4.75

(रिपोर्ट पृष्ठ सं-10(c) में संलग्न है)

5.3. शिक्षा ऋण Education loan

शिक्षा ऋण योजना के तहत बैंको का निष्पादन

(Amt. in crore)

Particulars	As on 30.06.18	As on 30.06.19				Total As on 30.06.19	GROWTH Y-O-Y IN EDU. LOAN	DISBURSEMENT DURING FY 2019-20
		Public Sector Bank	Private Sector Bank	RRB	Coop. Bank			
No. of Accounts	66458	63729	725	754	127	65335	(-)60.34	2467

Amount (In crore)	3148.48	3032.76	29.40	24.04	1.94	3088.14	164.84

(Annexure-10)

- वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही तक शिक्षा ऋण के तहत कुल 2467 खातों में 164.84 करोड़ रु की राशि के संवितरण की रिपोर्टिंग की गई है।
- RBI के प्रावधानों के तहत रु. 4.00 लाख तक के शिक्षा-ऋण में किसी भी तरह के SECURITY की आवश्यकता नहीं है, एवं रु.7.50 लाख तक के बिना SECURITY या GUARANTEE पर दिया गया शिक्षा ऋण पर CREDIT GUARANTEE उपलब्ध है, इसीलिये रु 7.50 लाख तक के शिक्षा-ऋण C.N.T या S.P.T एक्ट के प्रभाव से मुक्त माना जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए 54 वीं SLBC बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि SC/ST संवर्ग के योग्य छात्रों को रु.7.50 लाख तक के शिक्षा ऋण देने के लिए बैंकों के द्वारा विशेष अभियान चलाया जाय।
- इस वित्तीय वर्ष के दौरान कुल संवितरित ऋण में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को रु.7.50 लाख तक दिये गए शिक्षा ऋण की स्थिति (annexure -10 A) इस प्रकार है:

	स्वीकृत		वितरित	
	संख्या	राशि (रु करोड़ में)	संख्या	राशि (रु करोड़ में)
कुल दिया गया शिक्षा ऋण (2019-20)			2467	164.84
रु 7.50 लाख तक दिया गया कुल शिक्षा ऋण	1699	100.57	1656	37.05
अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को दिया गया रु 7.50 लाख तक दिया गया शिक्षा ऋण	382	23.34	368	9.06

5.4 आवास ऋण

आवास ऋण योजना के तहत बैंकों का प्रदर्शन

(रु.करोड़ में)

Particulars	Up to 30.06.18	30.06.2019				Total Up to 30.06.19	Growth in H/Loan Y-on-Y	Disburse ment in AFY 2019-20
		Public Sector Banks	Private Sector Banks	RRB	Coop. Banks			
खाता की सं.	78294	76233	5320	952	0	82505	642.83	3243
राशि	8642.05	8582.37	644.32	50.95	7.24	9284.88		483.07

Coop.Banks, Housing Loan की संख्या रिपोर्ट नहीं की है। (रिपोर्ट –annexure-11)

5.5 CREDIT FLOW TO SPECIAL CATEGORY OF BORROWERS (ऋण लेने वालों की विशेष श्रेणी हेतु ऋण प्रवाह)

5.5.1 अल्पसंख्यक समुदायों हेतु ऋण प्रवाह

30 जून, 2019 की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है

(रु. करोड़ में)

30 जून, 2018		% Share	30 जून, 2019		% Share
Total P.S.A	Loans to Minority Community		Total P.S.A	Loans to Minority Community	
45573.29	5806.86	12.74%	52754.89	6064.21	11.50%

(रिपोर्ट –annexure-13)

5.5.2 महिलाओं के लिए ऋण प्रवाह

30 जून, 2019 की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है

(रु. करोड़ में)

30 जून, 2018		PERCENTAGE OF CREDIT TO WOMEN	30 जून, 2019		PERCENTAGE OF CREDIT TO WOMEN
Gross Credit	Of which to Women		Gross Credit	Of which to Women	
86863.17	11455.11	13.19%	94952.77	13334.22	14.04%

(रिपोर्ट –annexure-13)

5.5.3 डीआरआई के लिए ऋण प्रवाह(DRI)

30 जून, 2019 को इस क्षेत्र में बैंकों के प्रदर्शन, नीचे इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

30 जून, 2018		DRI Percentage in Net Credit	30 जून, 2019		DRI Percentage in Net Credit
Net Credit	DRI		Net Credit	DRI	
86863.17	31.15	0.04%	94952.77	34.51	0.04%

(रिपोर्ट –annexure-12)

5.5.4. SC/ST के लिए ऋण प्रवाह

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लिए ऋण प्रवाह की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है- :

(रु. करोड़ में)

30 जून, 2018		% achievement	30 जून, 2019		% achievement
Net Credit	Loans to SC/ST		Net Credit	Loans to SC/ST	
86863.17	11288.26	12.99%	94952.77	11604.51	12.22%

(रिपोर्ट –annexure-13)

5.6. Scheme for financing of Women SHG

एसएचजी महिलाओं के वित्तपोषण हेतु योजना

बैंकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में पूरे राज्य में 185873 SHGs के S/B खाते हैं , जिनमें से 119644 खातों का credit linkage है, जिसमें कुल रु 935.95 करोड़ स्वीकृत किया गया है और वर्तमान में O/S राशि रु 611.36 करोड़ है |

(रिपोर्ट- Annexure-15)

5.7. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

एन आर एल एम की उपलब्धि (30 जून, 2019 तक) Source-JSLPS

संकेतक Indicators	Status as on March 2019	उपलब्धि Achievement in AFY- 19-20	Cumulative achievement till date since Inception
No of Blocks	263	-	263
No of Villages	21340	844	22184
Total No of SHGs supported By SRLM	193182	8990	202172
Total family supported by SRLM	2331272	209454	2540726
No of SHG receiving R.F	83006	2633	85639
Amt. of RF disbursed (Rs. in Lakhs)	12413	545	12958
No of SHG receiving CIF	37074	0	37074
Amt. of CIF disbursed (Rs. in Lakhs)	20527	0	20527
No of SHG credit linked with Banks	99746	5675	105421
Amt. of Credit availed from Banks (Rs. in Lacs)	97751	5675	103426

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम तिमाही के दौरान बैंको द्वारा SLBC के पोर्टल पर प्रदत्त जानकारी के अनुसार कुल 399 SHGs को credit लिंक किया गया है, जबकि JSLPS के द्वारा इस अवधि में credit linked किये गए SHGs की संख्या 5675 बताई गई है | JSLPS से अनुरोध है कि वे बैंको से अद्यतन जानकारी लेकर अपनी रिपोर्टिंग में आवश्यक सुधार कर सही आंकड़े SLBC को प्रेषित करें |

(JSLPS से प्राप्त SHG का बैंकवार एवं जिलावार प्रगति प्रतिवेदन पृष्ठ संख्या-13 (a) एवं 13 (b) में दिया गया है |)

कार्यसूची सं.	6
बैठक की तिथि	20.08.2019
बैठक की संख्या	68

**वित्तीय समावेशन एवं
प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)**

झारखंड में प्रधानमंत्री जन धन योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

A. BC (बैंक मित्र) द्वारा SSA के कवरेज की स्थिति

SSA की कुल संख्या	BC द्वारा SSA का coverage (Fixed Location)	बैंक शाखा द्वारा SSA का coverage	uncovered	No of Micro ATMs enabled & allotted to BCs	No of Pin Pads enabled & allotted to BCs
4178	3730	448	Nil	3252	5290

{रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या -14 (a) & 14 (b)}

B Online transaction करने वाले BC की स्थिति

बैंको द्वारा नियुक्त किये गए BC की कुल संख्या	Online transaction करने वाले BC की कुल संख्या	50 से कम प्रतिदिन transaction करने वाले BC की कुल संख्या	50 से 100 transaction प्रतिदिन करने वाले BC की कुल संख्या	100 से ज्यादा transaction प्रतिदिन करने वाले BC की कुल संख्या
6251	5379	3344	1288	747

{रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या -14 (c)}

C. PMJDY के तहत 30.06.2019 तक खोले गए खातों की स्थिति

30.06.2019 तक खोले गए खातों की संख्या			PMJDY खातों में जारी किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या	आधार Seeding किये गये PMJDY खातों की संख्या	मोबाइल Seeding किये गये PMJDY खातों की संख्या	बैंकों द्वारा वितरित किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या	बैंकों द्वारा activate किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या
ग्रामीण	शहरी	कुल					
A	B	C	D	E	F	G	H
9157656	3408016	12565672	10515989	11223920	8609010	8434120	7187806

{रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या -14 (d) & 14 (e)}

NB: (Coloumn A, B, C, D एवं E की जानकारी DFS portal से ली गई है जबकि Coloumn F, G एवं H में दी गई जानकारी बैंकों द्वारा दी गई है)

यद्यपि पीएमजेडीवाई योजना के तहत खोले गए खातों में अब तक कुल 10515989 रूपे कार्ड जारी किए गए हैं , परन्तु प्राप्त सूचना के आधार पर यह पता चल रहा है कि जारी किये गए रूपे कार्ड में से केवल 8434120 कार्ड ही अब तक वितरित किये गए हैं और उनमे से भी अब तक केवल 718706 खातों में रूपे कार्ड activate हो पाया है | बैंकों/LDMS से आग्रह है कि वर्तमान समय में Cashless transaction को बढ़ावा देने के लिए शत प्रतिशत रूपे कार्ड का activation करना अत्यंत जरूरी है , और BCs द्वारा किये जाने वाले प्रतिदिन transaction की संख्या को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किये जाने की आवश्यकता है |

राज्य में PMJDY खातों में दिये गए ओवरड्राफ्ट facility एवं death claim settlement से संबंधित बैंकों से प्राप्त आंकडा पृष्ठ संख्या-15 (a) में दर्शाया गया है |

**प्रधानमंत्री जन-धन योजना” के द्वितीय चरण में, जन सुरक्षा हेतु,
लागु किये गये, विभिन्न बीमा एवं पेन्शन योजनाएं :**

दिनांक: 30.06.2019 तक इन योजनाओं में सभी बैंकों की उपलब्धि निम्नवर्णित है-

PMJJBY	PMSBY	APY	
Total Enrolment	Total Enrolment	Enrolment during 2019-20	Total Enrolment since inception
764422	3279979	119704	373962

(रिपोर्ट पृष्ठ सं-15 (b) सलग्न है)

वित्तीय समावेशन एवं BRANCH EXPANSION पर भारतीय रिज़र्व बैंक का अद्यतन दिशानिर्देश एवं 5000 से ऊपर के गावों में बैंकिंग शाखा खोलने संबन्धित रोडमैप

भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व के निर्देशानुसार 5000 से ज्यादा आबादी वाले सभी गाँवों में दिनांक 31.03.17 तक बैंक की शाखा खोलना अनिवार्य किया गया था | झारखण्ड राज्य में ऐसे 259 गाँवों को चिन्हित किया गया था एवं पाया गया था कि इनमे से 122 गाँवों में ही बैंक की शाखा मौजूद है , बाकी के 137 गाँवों को विभिन्न बैंकों को आवंटित कर उन्हें brick & mortar branch खोलने के लिए सूचित किया गया था |

आरबीआई के नये दिशा निर्देश के अनुसार सप्ताह में कम से कम पांच दिन, प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे एक नियत स्थल पर कार्य कर रहे BC को 'बैंकिंग आउटलेट', माना जा सकता है | इस निर्देश के अनुसार निर्धारित सभी 137 गाँव में बैंक की शाखा या FIXED LOCATION BC खुल चुके हैं।

कार्यसूची सं	7
बैठक का दिनांक	20.08.2019
बैठक सं	68

एन पी ए & वसूली - एन पी ए/ बैंकों के स्ट्रेस्ड आस्तियों के रुकाव हेतु नियंत्रक उपाय एवं वसूली से संबन्धित उपाय

गैर निष्पादनीय आस्तियां

राज्य के बैंकों में दिनांक 30 जून 2019 को एन पी ए की स्थिति निम्नवत है :-

[राशि करोड़ में]

विवरण	30.06.2018	31.03.2019	30.06.2019	Variation over last FY
Advances	86863.17	95562.14	94952.77	(+)8089.6
Gross NPA	5099.35	5711.86	5866.98	(+)767.63
Provision	2571.05	2820.73	3025.41	(+)454.36
Net N.P.A	2528.30	2891.13	2841.57	(+)313.27
Percentage of Gross NPA	5.87%	5.98%	6.18%	(+)0.31
percentage of Net NPA	2.91%	3.02%	2.99%	(+)0.08

(रिपोर्ट- annexure-19)

झारखंड राज्य में बैंकों की गैर निष्पादनीय आस्तियां (N.P.A), एक चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुकी है | रु 5866.98 करोड़ का gross NPA, जो सकल अग्रिम का 6.18 % है , एक चिंताजनक आंकड़ा है | (विभिन्न segment में राज्य में मांग और वसूली से संबंधित आंकड़े annexure-17 एवं 18 में सलग्रक के रूप में दर्शाये गए हैं |)

सर्टिफिकेट केस का स्थिति

दिनांक 30 जून 2019 को राज्य के बैंकों में सर्टिफिकेट केस के लंबित मामलों की स्थिति इस प्रकार है:
[राशि करोड़ में]

Cases pending upto last quarter		Cases Filed during last Qtr.		Cases dispoed during last Qtr.		status as on 30.06.2018	
सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	संख्या	राशि
132699	213.39	3851	40.28	847	18.81	135703	234.86

(रिपोर्ट- annexure-20)

DRT केस की स्थिति

दिनांक 30 जून 2019 तक बैंकों के डी आर टी केसों की स्थिति इस प्रकार है :-

[राशि करोड़ में]

Cases pending as of last quarter		Cases Filed during last Quarter		Cases Resolved during last Quarter		Status as of 30.06.2018	
सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि
1920	874.75	201	112.62	448	229.89	1673	757.49

(रिपोर्ट- annexure-21)

SARFAESI केस की स्थिति

दिनांक 30 जून, 2019 तक SARFAESI cases की position निम्नवत है:

(Rs in Cr)

Notices Issued U/S 13 (2) of SARFAESI Act		Out of which symbolic possession taken under 13(4)		Request sent to Dist Authority for assistance in Physical Possession	Physical Possession taken	No. of cases pending at dist. level
A/C	Amt	A/C	Amt	A/C	A/C	A/C
4458	1877.27	1963	858.52	601	70	531

(रिपोर्ट- annexure-22)

ध्यातव्य हो कि ऋणियों के नाम के साथ बैंको से प्राप्त जिलावार आंकड़ों के अनुसार केवल 150 cases physical possession हेतु जिलों के अधिकारियों के पास लंबित पड़े हैं। बैंको से बार बार आग्रह के बावजूद इस रिपोर्ट एवं पोर्टल के रिपोर्ट में काफी भिन्नता है जिसपर सभी बैंको द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हालाँकि पूर्व में SLBC की बैठकों में दिए गए निर्देशानुसार SLBC द्वारा इन 150 cases की जानकारी राज्य सरकार को दे दी गयी है।

NB: SLBC द्वारा विभिन्न बैंको से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर PMEGP, KCC तथा PMMY योजनाओं के अंतर्गत दिए गए ऋण में NPA की स्थिति के आकलन का प्रयास किया गया है। यद्यपि बैंको द्वारा प्रेषित आंकड़ों में विसंगतिया है, परन्तु इन आंकड़ों के अध्ययन से NPA की बढ़ती समस्या का पता चलता है।

Scheme	No. of A/Cs	Amt of NPA (Rs in Cr)	% wrt advances in this sector
PMEGP	6994	120.20	32.45%
KCC	399736	1310.12	19.01%
PMMY	42121	736.82	18.29%

{रिपोर्ट पृष्ठ संख्या-18 (a) एवं 18 (b)}

कार्यसूची सं	8
बैठक का दिनांक	20.08.2019
बैठक सं	68

सरकार प्रायोजित कार्यक्रम

8.1 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

पीएमईजीपी के तहत आवेदनों के ई-ट्रैकिंग के लिए प्रस्तावित सेवाएँ अधिकांश बैंकों के द्वारा अपने वेबसाइट पर समाविष्ट कर ली गई हैं। इस प्रक्रिया के लिए KVIC के द्वारा सभी बैंकों को उनके द्वारा system number उपलब्ध कराने के पश्चात् User ID और Password दिये जाने का प्रावधान किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंकों द्वारा PMEGP लोन की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ही की जा रही है। SLBC द्वारा PMEGP पोर्टल से ली गई जानकारी के अनुसार दिनांक **30.06.2019** तक की स्थिति इस प्रकार है-

(राशि करोड़ में)

Forwarded to Banks		Sanctioned by Banks		Rejected/ Returned for rectification		Pending	
No	MM involved	No	MM involved	No	MM involved	No	MM involved
222	6.39	19	0.43	21	0.66	195	5.57

(पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक **30.06.2019** की स्थिति **annexure-14** पर दर्शायी गई है)

8.2 NULM & PMAY

शहरी विकास विभाग से प्राप्त NULM से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन रिपोर्ट संख्या-18 (a) में एवं PMAY से सम्बंधित प्रगति प्रतिवेदन रिपोर्ट संख्या-18 (b) में दर्शायी गई है।

शहरी विकास विभाग से प्राप्त **NULM से संबंधित** बैंकवार प्रगति प्रतिवेदन (SEP-I) रिपोर्ट संख्या-19 (a) एवं PMAY से सम्बंधित प्रगति प्रतिवेदन रिपोर्ट संख्या-19 (b) में दर्शायी गई है।

SEP-I (NULM) report as on 30.06.2019

No. of applications forwarded to Bank	No. of applications sanctioned	No of applications disbursed	No of applications pending
1611	1204	1090	407

PMAY Report (30.06.2019)

Source	Application submitted/received during the FY	No. of application sanctioned	Amt Sanctioned	No. of application rejected	No. of applications pending
Govt	2184	887	179.17	311	989
Banks	1772	1750	339.60	7	15

कार्यसूची संख्या	9
बैठक की तारीख	20.08.2019
बैठक संख्या	68

RSETI & FLCC का परिचालन

झारखंड राज्य में आरसेटी की वर्तमान स्थिति निम्नांकित है : (as of 30.06.2019)
झारखंड राज्य के 24 जिलों में निम्नलिखित सूची के अनुसार , विभिन्न बैंको के द्वारा 24 आरसेटी और 1 रुडसेटी संचालित किया जा रहा है |

बैंक ऑफ इंडिया	-	11 जिले
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	-	8 जिले
इलाहाबाद बैंक	-	3 जिले
पंजाब नेशनल बैंक	-	2 जिले
कुल		24 जिले
एवं रुडसेटी (रांची जिले की सिल्ली में केनरा एवं सिंडिकेट बैंक द्वारा संचालित)		1 जिला

AFY 2019-20 का वार्षिक लक्ष्य :

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या -582 ; प्रशिक्षनार्थियों की संख्या - 17460
उपलब्धि: प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या -117 प्रशिक्षनार्थियों की संख्या - 3253
{ विभिन्न RSETIs से प्राप्त रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या-19 (a)}

RSETI भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति,

कार्य सम्पूर्ण/ नये भवन में RSETI का संचालन	- 10
भवन निर्माण कार्य लगभग सम्पूर्ण	- 02
भवन निर्माण कार्य प्रगति पर	- 12
भवन निर्माण से संबंधित कोई भी कार्य प्रारंभ होना बाकी	- 01

- बोकारो, चतरा, धनबाद, पूर्वी सिंघभूम, गुमला, खूंटी, कोडरमा, सिमडेगा, देवघर एवं सराइकेला में भवन निर्माण का कार्य सम्पूर्ण हो गया है परन्तु सराइकेला में RSETI का कार्य नए भवन में प्रारंभ नहीं हो सका है |
 - गिरिडीह एवं जामतारा में भवन निर्माण का कार्य लगभग समाप्ति पर है |
 - रामगढ़ में निर्माण कार्य से सम्बंधित अंतिम निर्णय होना बाकी है |
- (सभी RSETI निदेशकों से प्राप्त विवरणी पृष्ठ सं-20 (b) से 20 (d) में संलग्न है)

RSETI प्रशिक्षार्थियों की बैंकों से वित्तीय संबन्धता (CREDIT LINKAGE) की स्थिति :

AFY 2018-19 के दौरान		AFY 2019-20 के दौरान	
कुल प्रशिक्षनार्थी	कुल प्रशिक्षनार्थी	कुल प्रशिक्षनार्थी	Credit Linked
17970	17970	3253	-

(विभिन्न RSETIs से प्राप्त रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या-19 (e) एवं 19 (f) पर उपलब्ध है)

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (FLCCs) का संचालन

वर्तमान में 24 वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (FLCCs) झारखंड के राज्य में परिचालन कर रहे हैं :

बैंक का नाम	बैंक वित्तीय साक्षरता केन्द्र परिचालन (जिला स्तर पर)	संख्या
बीओआई	रांची, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम (पश्चिम), सिंहभूम (पूर्वी), गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, चतरा, खूंटी, सराइकेला, सिमडेगा	15
एसबीआई	देवघर, पाकुर, साहिबगंज, जामताड़ा, गढ़वा, लातेहर, पलामू	7
इलाहाबाद बैंक	दुमका व गोड्डा	2

उपरोक्त बैंको के अलावा निम्नलिखित ग्रामीण बैंको के शाखाओं द्वारा भी वित्तीय साक्षरता केन्द्र का सञ्चालन किया जाता है ,

झारखण्ड ग्रामीण बैंक - 15 केन्द्र ; वनांचल ग्रामीण बैंक - 9 केन्द्र

इसके अलावे झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक भी पिछले कुछ महीनों से 3 वित्तीय साक्षरता (रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम) केंद्र का संचालन कर रही है।

अप्रैल-जून 2019 तिमाही के दौरान आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर

तिमाही में आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर की संख्या	
वित्तीय साक्षरता केंद्र द्वारा	1466
ग्रामीण शाखाओं द्वारा	3329
कुल	4795

{रिपोर्ट-पृष्ठ संख्या-20 (a) एवं 20 (b) पर उपलब्ध है}

कार्यसूची सं	10
बैठक की तारीख	20.08.2019
बैठक संख्या	68

एसएलबीसी के विभिन्न उप समितियों के कामकाज

पहले के एसएलबीसी की बैठकों में लिए गए निर्णय के संदर्भ में, एसएलबीसी के निम्नलिखित उप-समितियां कार्य कर रही हैं। उप-समितियों से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:

एस.एल.बी.सी की उप समितियां

Sr. No	उप समिति के नाम	उप समिति के पदधारी	उप समिति के अन्य सदस्य	संदर्भ	पिछली बैठक की तिथि
1.	कृषि तथा संबद्ध उप समिति	प्रमुख सचिव / सचिव (कृषि) GOJ संयोजक – नाबार्ड	1)प्रमुख सचिव/ सचिव संस्थागत वित्त 2)प्रमुख सचिव/, सचिव जल संसाधन विभाग। 3) सचिव, वन विभाग। 4) नाबार्ड प्रमुख महाप्रबंधक या डीजीएम के स्तर के बराबर 5) संयोजक बैंक एसएलबीसी (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 6) एसबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 7) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 8) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 9) रजिस्ट्रार सहकारी समितियां	1)कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां, (केसीसी सहित) 2)नई परियोजना/स्कीम (कृषि) 3) कृषि ऋण देने के लिए क्षमता का विकास	09.07.2019

2.	निर्यात संवर्धन	एसएलबीसी के संयोजक बैंक - संयोजक एसएलबीसी	<ol style="list-style-type: none"> 1) प्रमुख सचिव /सचिव स्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन 2) भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग. एजीएम 3) स्थानीय निर्यात संस्था 4) उद्योग विभाग 5) एक्जिम बैंक 6) अन्य सदस्य बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई, और पीएनबी 	<ol style="list-style-type: none"> 1) निर्यात क्रेडिट के तहत ऋण देने की प्रगति की समीक्षा 2) हस्तकला /कृषि के निर्यात में सुधार के लिए सुझाव 3) निर्यात संवर्धन के लिए सक्षम कारकों का प्रोत्साहन 	09.05.2019
3.	सुरक्षा	प्रमुख सचिव / सचिव (गृह) GOJ संयोजक- एसबीआई	<ol style="list-style-type: none"> 1) एडीजी / पुलिस महानिरीक्षक - परिचालन 2) प्रमुख सचिव /सचिव संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ 3) आरबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 4) संयोजक बैंक एसएलबीसी (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 5) एसबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 6) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 7) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 8) झारखंड ग्रामीण बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) बैंक के ट्रेजरी की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा 2) राज्य की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा / नक्सल क्षेत्र में विशेष रूप से चर्चा 3) बैंक डकैती के मामलों में अंतिम रिपोर्ट 4) बैंक शाखाओं / करेंसी चेस्ट में पुलिस बल की तैनाती 	31.12.2018
4.	सीडी अनुपात और एसीपी उप-समिति	एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक - एसएलबीसी	<ol style="list-style-type: none"> 1) प्रमुख सचिव /सचिव संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ. 2) भारतीय रिजर्व बैंक 3) नाबार्ड 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) पंजाब नेशनल बैंक 	<ol style="list-style-type: none"> 1) एसीपी की निगरानी उपलब्धि एवं अनुमानित सीडी अनुपात 2) खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए विशेष रणनीति 	09.05.2019

			7) झारखंड ग्रामीण बैंक 8) केनरा बैंक 9) यूनियन बैंक	3) एसीपी के तहत ऋण देने में वृद्धि के लिए कारकों को सक्षम करने का विकास	
5.	एसएलबीसी परिचालन समिति	एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक - एसएलबीसी	1) संस्थागत वित्त विभाग 2) भारतीय रिजर्व बैंक 3) नाबार्ड 4) निदेशक, उद्योग 5) आईसीआईसीआई बैंक 6) केनरा बैंक 7) पंजाब नेशनल बैंक 8) बैंक ऑफ इंडिया 9) भारतीय स्टेट बैंक	1) नवीनतम स्थिति और सरकार /बैंकों के पास लंबित मुद्दें 2) एसएलबीसी कामकाज में सुधार (बैंक /सरकार)	09.05.2019
6.	विधानमंडल और अन्य मुद्दे पर उप समिति	सचिव, संस्थागत वित्त संयोजक- एसएलबीसी	1) सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, सहकारी 3) सचिव, राजस्व 4) सचिव, कृषि 5) सचिव, योजना 6) भारतीय स्टेट बैंक 7) बैंक ऑफ इंडिया 8) इलाहाबाद बैंक 9) भारतीय रिजर्व बैंक	विधानमंडल से संबंधित मुद्दों पर, राज्य में ऋण के माध्यम से विकास के लिए संशोधन और अन्य गतिविधियों के लिए राज्य सरकार एवं बैंकों से चर्चा	02.02.2015
7.	एमएसएमई और सरकार प्रायोजित योजनाओं पर उप-समिति	सचिव, (ग्रामीण विकास) संयोजक- बीओआई	1) सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, संस्थागत वित्त 3) सचिव, उद्योग 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक	सरकार के तहत प्रायोजित योजनाओं में एमएसएमई वित्तपोषण और वित्तपोषण से संबंधित सभी मुद्दे,	09.05.2019
8	आवास वित्त पर उप-समिति	सचिव (शहरी विकास) संयोजक- एसबीआई	1) सचिव, शहरी विकास 2) सचिव, वित्त 3) राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रतिनिधि 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक 7) दोनों ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष	आवास वित्त पोषण से संबंधित सभी मुद्दें (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र)	01.03.2019
9	SHG-Bank Linkage एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर उप-समिति	सचिव (ग्रामीण विकास) संयोजक - झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी	1) प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, वित्त 3) भारतीय रिजर्व बैंक 4) एसएलबीसी 5) भारतीय स्टेट बैंक	आजीविका संवर्धन रणनीतियों पर राज्य स्तर समर्थन- झारखंड	20.11.2018

			6) बैंक ऑफ इंडिया 7) केनरा बैंक 8) पी.एन.बी. 9) झारखण्ड ग्रामीण बैंक 10) नाबार्ड		
10	RSETIs पर उप-समिति	सचिव (ग्रामीण विकास) संयोजक - झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी	1) प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, आईएफ और पीआई, GoJ 3) भारतीय रिजर्व बैंक 4) एसएलबीसी 5) नाबार्ड 6) भारतीय स्टेट बैंक 7) केनरा बैंक 8) पी.एन.बी. 9) राज्य निदेशक, RSETI	RSETI में प्रशिक्षण एवं उसके उपरांत बैंकों से Credit Linkage से सम्बन्धित मुद्दे	20.11.2018
11	NPA पर उप समिति	सचिव, संस्थागत वित्त संयोजक- एसएलबीसी	1) सचिव, संस्थागत वित्त 2) एसएलबीसी 3) भारतीय रिजर्व बैंक 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक 7) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 9) केनरा बैंक 10) UCO Bank	राज्य में NPA एवं recovery की स्थिति; DRT, Certificate एवं SARFAESI cases	09.05.2019

कार्यसूची सं.	11
बैठक की तिथि	20.08.2019
बैठक सं.	68

विविध कार्यसूची

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 17-10/2018-CSIS दिनांक 10.01.2019 के आदेश के आलोक में राज्य के मुख्य सचिव के निर्देशानुसार SLBC द्वारा सभी बैंको से विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर लंबित शिक्षा ऋण आवेदनों की जानकारी मांगी गयी थी | अद्यतन जानकारी रिपोर्ट 26 (a) एवं 26 (b) के अनुसार राज्य में 1529 आवेदन लंबित है। इससे विदित होता है कि इस दिशा में बैंको द्वारा पूर्ण रूप से प्रयास नहीं किया जा रहा है। **(Action: सभी बैंक)**

2. वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 28.06.2019 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'MSME SUPPORT AND OUTREACH Campaign'-द्वितीय चरण के क्रियान्वन करने का निर्देश दिया। द्वितीय चरण 1 जुलाई 2019 से 15 अगस्त 2019 तक देश के सभी जिलों में चलाई जा रही है। इस विषय पर एसएलबीसी ने राज्य के सभी अग्रणी जिला प्रबंधक एवं बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों के साथ 23 जुलाई 2019 को एसएलबीसी सभागार में बैठक की थी। राज्य के सभी अग्रणी जिला प्रबंधक ने अपने जिले में लक्ष्य चिन्हित किया है। इस अभियान के तहत पूरे राज्य में 55191 एमएसएमई कवर किया गया। इस अभियान के अंतर्गत अभी तक की प्रगति संलग्न है। **(Action: सभी सम्बंधित बैंक एवं LDM)**

3. **KCC SATURATION DRIVE** – कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 4 फरवरी 2019 पूरा देश के सभी राज्यों में केसीसी सैचुरेशन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 4 जुलाई 2019 को देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कृषि मंत्रालय द्वारा अभियान को सफल बनाने के लिए पत्र लिखा गया है। पत्र की कॉपी सभी एसएलबीसी को भी दी गई है। इस अभियान के तहत सभी जिलों में Gap Analysis करके एलडीएम के माध्यम से एसएलबीसी को हर जिले का लक्ष्य निर्धारित करना था। इस लक्ष्य को पूरे राज्य में निर्धारित करके के उपरांत सभी बैंक को प्रेषित कर दिया गया है। सभी योग्य किसानों को केसीसी मिलने के उपरांत जिले के उपायुक्त केसीसी सैचुरेशन सर्टिफिकेट कृषि मंत्रालय को प्रेषित करेंगे। इस अभियान के तहत झारखंड राज्य में कुल 388024 किसान क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अभियान से संबंधित रिपोर्ट संलग्न है। **(Action: सभी सम्बंधित बैंक एवं LDM)**

4. **APY CITIZEN'S CHOICE 2019 CAMPAIGN-** PFRDA द्वार 1 अगस्त 2019 से 31 अगस्त 2019 तक पूरे देश भर में APY CITIZEN'S CHOICE 2019 CAMPAIGN की शुरुआत

की गई है। इस अभियान से संबंधित लक्ष्य सभी जिला एवं बैंक को एसएलबीसी के द्वारा प्रेषित किया जा चुका है श्रेष्ठ एसएलबीसी, एलडीएम, तथा बैंक को PFRDA द्वारा नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। इस अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले LDM तथा बैंक को अगले एसएलबीसी बैठक में भी पुरस्कृत किया जाएगा। इस अभियान के तहत राज्य के 2 जिले रांची एवं पूर्वी सिंहभूम में अटल पेंशन योजना पर टाउन हॉल मीटिंग का आयोजन अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा करवाया जाएगा। **(Action: सभी सम्बंधित बैंक एवं LDM)**

5. DFS द्वारा identified 440 centres पर BC की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में हुई चर्चा के दौरान JRGB के द्वारा 4 centres पर BC नियुक्त नहीं किया गया है, कुल 15 बचे हुए स्थानों में से 11 स्थानों पर JRGB द्वारा BC नियुक्त कर लिए जाने की बात कही गयी है। **(Action: JRGB)**

7. RBI के निर्देशानुसार 2000 से 5000 जनसंख्या वाले ग्राम में बैंकिंग सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है। इसके लिए इस श्रेणी के सभी गाँव चिन्हित कर बैंकिंग सुविधा कवरेज सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक जानकारी की सूची पूर्ण करने के लिए राज्य के सभी एलडीएम को लिखा जा चुका है। आठ जिलों में 152 गाँव ऐसे चिन्हित हुए हैं जिन्हें बैंकिंग आउटलेट से तुरंत करना है। इसकी सूची जिलों को दे दी गयी है।

8. वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के 22 जुलाई 2019 के पत्र के अनुसार झारखंड राज्य के 794 गाँव को जन धन दर्शक पोर्टल पर UNCOVERED पाया गया है। इस संबंध में 26 जुलाई 2019 को वित्तीय सेवाएं विभाग के संयुक्त सचिव श्री भूषण कुमार सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी एसएलबीसी व बैंकों के प्रधान कार्यालय से बैठक की। बैठक के आधार पर 30 जुलाई 2019 तक सभी गाँव का बैंकिंग आउटलेट से कवरेज रिपोर्ट PMJDY FI-PLAN पोर्टल पर एसएलबीसी को अपलोड करना था। अद्यतन जानकारी के अनुसार राज्य के 794 गाँव में से 652 गाँव 5 किलोमीटर के रेडियस में बैंकिंग आउटलेट द्वारा कवर किया जा चुका है। शेष 142 गाँव राज्य के 11 जिलों में अवस्थित हैं। इन जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक के द्वारा 142 गाँवों को बैंकिंग आउटलेट द्वारा कवर करने के लिए बैंकों में आवंटन कर दिया गया है और उन सभी बैंकों से आग्रह किया गया है कि 15 अगस्त 2019 तक सभी बैंकों को आवंटित गाँव को बैंकिंग आउटलेट से कवर कर लिया जाएगा। इस संबंध में सभी संबंधित बैंकों को गाँवों को कवर करने वाले बैंकिंग आउटलेट्स एवं गाँव का विवरण तथा Longitude लाटीट्यूड जन धन दर्शक जी आईएस वेब पोर्टल पर अपडेट करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस विषय पर अद्यतन रिपोर्ट में संलग्न है।

11. Agri Clinics/Agri Business- कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित इस केंद्रीय सेक्टर योजना से संबंधित दिशा-निर्देश केंद्रीय विद्यालय मुंबई के परिपत्र संख्या 145/आईसीडी-35/2011 दिनांक 2 अगस्त 2011 के माध्यम से निर्गत किए गए हैं उल्लेखनीय है कि इस योजना अंतर्गत कृषि संकाय के स्नातकों डिप्लोमा होल्डर्स इत्यादि को कृषि क्लिनिक व कृषि व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट मैनेज के माध्यम से 2 माह का पूर्णता निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है और तत्पश्चात बैंक ऋण के माध्यम से जोड़ने का प्रावधान है पूर्ण विराम योजना अंतर्गत बैंक वित्त पोषित लाभार्थियों को भारत सरकार से 36 से 44 वर्ष तक के अनुदान का भी प्रावधान है।

इस योजना के माध्यम से बैंकों द्वारा जहां एक और स्वरोजगार स्थापना को बढ़ावा मिलेगा वहीं दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में ऋण की संभावनाओं में भी वृद्धि होगी अतः बैंकों का अपेक्षित सहयोग आवश्यक है योजना की विस्तृत जानकारी व दिशानिर्देश वेबसाइट www.manage.gov.in पर उपलब्ध है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 04. जून 2019 को ईमेल से इस योजना को एसएलबीसी की बैठक में नियमित रूप से शामिल करने का आग्रह किया गया है इस संबंध में ऋण स्वीकृत करने पर इसका रिपोर्ट एसएलबीसी को सभी बैंक नियमित रूप से देना सुनिश्चित करेंगे।



कार्यसूची सं.	12
बैठक का दिनांक	20.08.2019
बैठक सं	68

Less cash/Digital बैंकिंग

- माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा less cash economy को बढ़ावा देने के लिए किये गए आह्वाहन पर झारखण्ड राज्य ने त्वरित प्रतिक्रिया दिखाई और इसके तहत राज्य में digital transaction को लोकप्रिय बनाने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं-जिनमे Mobile App download करना और सभी नागरिकों को cashless transaction से जुड़े विभिन्न उत्पादों की जानकारी देना है | इसके साथ ही सभी इच्छुक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में POS machines देने की प्रक्रिया भी की जा रही है | राज्य के सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों/बैंकों द्वारा अपने जिले/बैंकों में इसके लिये नियमित प्रयास किये जा रहे हैं | इन प्रयासों की बदौलत दिनांक 30.06.2019 तक राज्य में कुल 32507 POS machines का installation कराया जा चुका है जो demonetization के पूर्व यानि दिनांक 09.11.2017 तक केवल 6399 था | यद्यपि यह उपलब्धि संतोषजनक है परंतु इस दिशा में अभी और कार्य किये जाने की आवश्यकता है | इसके साथ ही सभी बैंको द्वारा पूरे राज्य में लगभग 3.63 लाख credit card, 2.00 करोड़ debit कार्ड, एटीएम, rupay कार्ड आदि और 25.66 लाख net banking की सुविधा अपने ग्राहकों को दी गई है |

{प्रगति प्रतिवेदन सलग्न-पृष्ठ सं-27 (a)}

कार्यसूची सं.	13
बैठक का दिनांक	20.08.2019
बैठक सं	68

NATIONAL BAMBOO MISSION/राष्ट्रीय बाँस मिशन

बाँस की खेती के लिए नई राह प्रशस्त करने और अच्छी संभावना वाले राज्यों में इसकी मूल्य शृंखला के समग्र विकास के लिए भारत सरकार द्वारा 2018-19 के दौरान पुनः संरचित राष्ट्रीय बाँस मिशन प्रारंभ किया गया था। पुनः संरचित राष्ट्रीय बाँस मिशन में कई गतिविधियों का प्रावधान है जिनमें ऋण से जुड़ी सब्सिडी घटक शामिल है। नाबार्ड ने भी बैंकों के लिए ऋण अवसरों को निर्देशित करते हुए भारत में बाँस के विकास की एक समन्वित नीति तैयार की है इसे दिनांक 15 फरवरी 2019 को नाबार्ड के पत्र संख्या राबै 1/प्र.का/1317/सी-टैग/पॉलिसी बी- कीपिंग एंड बैम्बू/ 2018-19 के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी बैंक को एवं एसएलबीसी को भेजा गया था। उस पत्र की कॉपी एसएलबीसी झारखंड द्वारा राज्य स्थापित सभी बैंकों के नियंत्रक कार्यालय को 5 अगस्त 2019 को पुनः प्रेषित किया गया है। नाबार्ड द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से बाँस क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह की सुविधा के बारे में सभी हितधारकों को अवगत कराने के लिए तिमाही बैठक में इस योजना को कार्यसूची के रूप में शामिल करने का आग्रह किया गया है। बैंकों के सभी नियंत्रक प्रमुख से आग्रह है कि इस दिशा में कार्य किया जा सकता है।

कार्यसूची सं.	14
बैठक का दिनांक	20.08.2019
बैठक सं.	68

DOUBLING OF FARMERS INCOME BY 2020

वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए पांच प्रमुख अर्थात् उत्पादकता पानी और कृषि इनपुट की नीतियों में सुधार के द्वारा आय में वृद्धि एकीकृत कृषि प्रणाली बेहतर बाजार मूल्य प्राप्ति और विशेष नीतिगत उपाय अपनाए जा रहे हैं किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित मानकों से संबंधित मुद्दों पर सुधा स्तर पर ध्यान देना आवश्यक है ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर वांछित परिणाम हासिल हो सके:-

- क) कम लागत के उपकरण तथा विस्तार सेवाओं के माध्यम से उत्पादन
- ख) कृषि के लिए लाभकारी मूल्य का बाजार
- ग) पूरे वर्ष के दौरान लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए उपाय
- घ) जोखिम को कम करने के लिए जीवन और उत्पादन जोखिम के मुद्दों पर ध्यान
- च) अन्य:-

i) उत्पादकता बढ़ाने लागत को कम करने जल उपयोग दक्षता में सुधार हेतु टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल

ii) इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्टिविटी में सुधार

ई) कृषि रिन सुधार में संस्थागत वित्त संस्थानों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में परिवर्तन

किसानों के सपोर्ट के लिए मूल्य निर्धारण सब्सिडी न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा फसल बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध करवाना आवश्यक है।

सरकार आय केंद्रितता पर ध्यान केंद्रित करके कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य बना रही है। किसान के लिए शुद्ध सकारात्मक रिटर्न का एहसास करने के लिए, राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से प्रमुख रूप से योजनाओं का प्रचार और कार्यान्वयन किया जा रहा है: - मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) योजना; नीम लेपित यूरिया (NCU); प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY); परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY); राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना (ई-एनएएम); प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना—(पीएमएफबीवाई); राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम); बागवानी के विकास के लिए मिशन (MIDH); तिलहन और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन (NMOOP); स्थायी कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए); कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (NMAET) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)। इसके अलावा, वृक्षारोपण (हर मेध पार पेड), मधुमक्खी पालन, डेयरी और मत्स्य पालन से संबंधित योजनाएं भी लागू की जाती हैं। ये सभी योजनाएँ कृषि के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की जाती हैं और जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

कार्यसूची सं.	15
बैठक की तिथि	20.08.2019
बैठक सं	68

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा ...

65वीं SLBC बैठक की प्रस्तावित तिथि : 28 नवम्बर 2018

